

ई-गवर्नेस पर क्षेत्रीय सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

दिनांक : 09 जनवरी 2024, मंगलवार	समय : 2.00 PM	स्थान : खानापाड़ा, गुवाहाटी
---------------------------------	---------------	-----------------------------

- माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जी,
- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास जी,
- संयुक्त सचिव श्री एन.बी.एस. राजपूत जी,
- असम सरकार के मुख्य सचिव श्री ऍबन कुमार बरठाकुर जी,
- उपस्थित अन्य अतिथिगण,
- असम सरकार के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण,
- मीडिया के हमारे मित्रों,

नमस्कार !

ई-गवर्नेस पर ऍ योजित इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहां इस सम्मेलन का ऍ योजन करने के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को धन्यवाद देता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन डिजिटल ऍरिवर्तन के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के दृष्टिकोण के क्रियान्वयन में ऍ गे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

मुझे यह भी विश्वास है कि यह अनूठी ंहल ं म नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस की ं वश्यकता और उ॒योगिता को ंरिप्रेक्ष्य में रखने में सहायक होगा।

यह दो दिवसीय सम्मेलन ई-गवर्नेंस की उ॒योगिता के बारे में लोगों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता ंदा करने की दिशा में एक महत्व॒पूर्ण कदम है। यह सरकार के कामकाज और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के तरीके को सरल बनाने में भी उ॒योगी होगा।

मैं इस सम्मेलन से जुड़े सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से इस विचार-मंथन कार्यक्रम की कल्ा, डिजाइन और क्रियान्वयन करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि अ॒नी विशेषज्ञता से इस सम्मेलन को प्रभावी और कुशल बनाएंगे।

मित्रों,

हमारी सरकार भारत को डिजिटल रू॒ से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया के स॒ने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ंांचा बनाने के लिए सक्रिय रू॒ से काम कर रहे हैं, जो हमारे नागरिकों के हितों की सेवा करेगा और उनके जीवन को बदल देगा।

ई-गवर्नेस हमारे डिजिटल इंडिया के सपने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिन प्रौद्योगिकियों को हम शासन में शामिल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य हमारे जीवन को सरल और सजान बनाना है। ई-गवर्नेस प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और कई बाधाओं को दूर करता है, जो काम की गति और प्रगति को धीमा कर रहे हैं। ई-गवर्नेस पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, कार्रवाई की समयबद्धता और कार्य में देरी को समाप्त करता है। यह लागत को कम करता है तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करता है।

जब हम ई-गवर्नेस की बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में सबसे पहले “मोबाइल” का ध्यान जाता है, जो एम-गवर्नेस (मोबाइल गवर्नेस) के महत्व को दोहराता है। यह मोबाइल गवर्नेस परियोजना मोबाइल फोन के माध्यम से बिल भुगतान, ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक जुर्माना भुगतान जैसी अन्य उपयोगिता सेवाएं उपलब्ध कराती है।

यह सेवाओं के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकार और नागरिकों को जोड़ने के लिए एक व्यापक नागरिक मंच “सेवा सेतु” तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला असम ँ ईटी का एक अग्रणी केंद्र है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच जुड़ाव की एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और शासन को एकजुट रूप से विलय किया है, जो कि सराहनीय है।

मुझे खुशी है कि असम में भी ई-गवर्नेंस डिजिटल असम कार्यक्रम की प्रमुख ँहलों में से एक है। असम के नागरिक अब प्रमाण-पत्रों के लिए ँ वेदन करना, करों का भुगतान करना और सरकारी योजनाओं के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मुझे खुशी है कि राज्य सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमि अभिलेखों के डिजिटलिकरण एवं मानचित्रण के लिए “मिशन वसुंधरा”, सचिवालय में ँ धिकारिक फाइलों के डिजिटलिकरण के लिए “मिशन सद्भावना”, ँशनभोगियों के लिए “कृतज्ञता पोर्टल” एवं “जीवन प्रमाण” जैसी ँरियोजनाएं चला रही हैं। इससे सरकारी कामकाज और नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है।

इसके अलावा “केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली” (CPGRAMS) असम सरकार के सभी विभागों को जोड़ने वाला एकल पोर्टल है, जिसमें 1 म नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से एक सशक्त राष्ट्र बनाने की राह पर अग्रसर है। हमारी युवा ऊर्जा हमारे राष्ट्र के लिए बेशकीमती संपत्ति है। इसलिए, हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौशल विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं।

मित्रों,

1 ज हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करके जिस पैमाने और गति से प्रगति कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पारंपरिक पद्धति की जगह प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए हितधारकों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

नागरिकों को ई-गवर्नेंस पहल का पूरा लाभ उठाने के लिए खुद को तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुरूप ालने की जरूरत है। इसलिए, इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

ई-गवर्नेस की सफलता पूरी तरह से प्रक्रियात्मक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन के सफल और सुचारु प्रबंधन पर निर्भर करती है।

ई-गवर्नेस सेवाएं जैसे जीवन प्रमाण, डिजिटल लॉकर सिस्टम, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-अस्पताल-ओपीडी ऑनलाइन (ओरएफ), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-कोर्ट, डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-संयुक्त आदि सभी ई-गवर्नेस की शाखाएं हैं।

अगर हमें डिजिटल की अभूतपूर्व वृद्धि का उपयोग करना है, तो हमें उन्हें निरंतर संशोधित करने की आवश्यकता है। हमें संस्थागत संरचनाओं, कानूनी और नियामक रूढ़िरेखा और सूचना लेनदेन प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा।

मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समावेशी विकास और परिवर्तन लाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सराहना करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन कई नवीन विचारों का केंद्र बिंदु बनेगा, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र की मदद करेगा।

यह हमारे सिस्टम और नागरिकों को ई-गवर्नेंस को एक उ॒पकरण के रू॒ में ई-गवर्नेंस का तेजी से उ॒योग करने के लिए सशक्त बनाएगा ताकि ॒ म नागरिक हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अवसरों का लाभ उठा सकें और 2047 तक विकसित भारत की ॒रिकल्॒ना को साकार किया जा सके।

इस दो दिवसीय सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।